Proposal for New Urban Banks

*310. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has rejected 88 out of the 90 proposals for new urban banks received in 2002-03;

(b) if so, whether the cooperative banking sector has been under Reserve Bank of India scanner for over last two years;

(c) whether in its report on trends and progress of banking in India in 2002-03, the Reserve Bank of India has given details of a mechanism put in place to streamline the cooperative banking; and

(d) if so, the other reasons for rejecting the 88 proposals?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (d) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Reserve Bank of India (RBI) has reported that out of 88 proposals for opening new Urban Cooperative Banks (UCBs) in the country, the Screening Committee constituted by RBI has recommended approval for only two proposals during 2002-03.

(b) Urban co-operative banking sector in some areas was facing a certain level of criris on account of irregularities committed by a few UCBs which led to substantial losses. RBI was, therefore, required to initiate specific regulatory and supervisory measures to address bank specific problems and to avoid the recurrence of irregularities.

(c) and (d) Yes, Sir. The Report on Trend and Progress of Banking in India in 2002-03, details the measures and other regulatory initiatives taken by the RBI during the year. RBI has set up a Committee of experts to screen proposals for new UCBs. The Committee takes into account the policy environment of the concerned State, track record and integrity of the promoters, requirements under prudential norms and the state of urban banking in the concerned State. The Committee has not recommended approval for the remaining proposals for various reasons like lack of

confidence in the promoters' profile, their lack of professionalism, unrealistic business projections, defaulter status of some of the promoters, etc.

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: सभापति महोदय, पिछले तीन-चार साल में देश में करीब 23 सहकारी बैंक बंद हुए हैं। मंत्री जी ने भी अपने जवाब में कहा है कि कुछ सहकारी बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं की वजह से संकट पैदा हुआ है। क्या सरकार यह मानती है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार इस अनियमितता को रोकने में नाकाम रही है क्योंकि जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि ''भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विशिष्ट नियामक और पर्यवेक्षी उपाय शुरू करने पड़े।'' इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वे विशिष्ट नियामक और पर्यवेक्षी उपाय कौन से हैं? इसके अतिरिक्त जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो घोटाले हुए हैं, वे रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफिस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिली भगत से हुए हैं जिसमें सत्ताधारी पक्ष के कुछ राजकीय लोग भी शामिल हैं.....

श्री सभापति: आप क्वेश्चन पूछिए।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं जानती हूं कि जो लोग हाउस में उपस्थित नहीं हैं, उनका नाम हाउस में नहीं लिया जाता इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं। * की गौरव यात्रा के दक्षिण गुजरात के जो सारथी थे, * या.....

श्री सभापति: नाम नहीं लीजिए। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: या बीजेपी के जो एक्स एम पी थे, वे भी इसमें शामिल हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपने नाम ले लिया है और मैं इसको ऐक्सपंज करता हूं।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री सभापति: आप क्वेश्चन पूछिए न?

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: मैं वही कह रही हूं कि इन लोगों के खिलाफ.....

श्री सभापति: यह क्वेश्चन नहीं है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: और रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है? ...(व्यवधान)... वे उपाय कौन से हैं ...(व्यवधान)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती सविता शारदा: महोदय, ये प्रश्न पूछ रही हैं या आक्षेप लगा रही हैं? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: मैं नाम लेना चाहती। मैंने पहले ही कहा था। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपने नाम ले दिया है। नाम लेना क्या नहीं चाहती?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जानना चाहा है कि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उसके पीछे कोई अनियमितता है? परिस्थिति में कुछ बिगाड़ हुआ है, तभी तो यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर सब कुछ ठीक चलता तो परिस्थिति उत्पन्न कैसे होती? जहां तक कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रश्न है, जैसा कई बार मैं उल्लेख कर चुका हूं, अभी हाल में ऐसी परिस्थिति है जहां ट्राएंगुलर कंट्रोल है। स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है, केन्द्रीय सरकार का भी है और रिजर्व बैंक का भी है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, मेरा विचार है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो इस प्रकार की अनियमितताएं या कमियां हम देखते हैं, उनमें सुधार होना कठिन है।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: महोदय....

श्री सभापति: दूसरी सप्लीमेंटरी जल्दी करेंगी तो करने दूंगा।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: जल्दी बोलूंगी किन्तु मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए।

श्री सभापति: सीधा प्रश्न करिए।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: आपने अभी कहा कि डुएल कंट्रोल की वजह से यह सब हो रहा है। इस डुएल कंट्रोल को मिटाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं.....

श्री सभापति: साथ ही नहीं, क्या सोच रहे हैं, यही बता दीजिए।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: महोदय, प्रश्न तो यही है कि जहां बैंक बंद हुए हैं और दूसरे बैंक खोलने के लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, वहां के लोगों के लिए आपने क्या उपाय सोचे हैं? क्या सरकार वहां नए बैंक खोलने जा रही है?

श्री सभापति: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री जसवंत सिंह: अनियमितताएं या ट्राएंगुलर कंट्रोल हटाने के लिए सरकार ने लेजीस्लेशन बनाया है। वह अभी सदन के सामने आएगा। जब सदन की स्वीकृति मिलेगी, तभी यह सुधार हो पाएगा। उससे पहले कि वह सदन के सामने आए, कई राज्य सरकारों में इस बात को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो गयी है। आज ही मुझे एक राज्य से एक डेलीगेशन मिलने वाला है कि ऐसा सुधार न लाइए। इस प्रकार सुधार लाना है या नहीं लाना--उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि वहां, जहां बैंक बंद हुए हैं, आप क्या करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जब सुधार आ जाएगा तो बैंक खुल जाएंगे।

श्री सभापति: डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी।

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय.....

श्री सभापति: पहले उनको प्रश्न करने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। हाउस में ठंडक है और आप हुक्मदेव नारायण जी को देख लीजिए। कृपया थोड़ा टेम्प्रेचर बढ़वा दीजिए, उनको ठंड लग रही है। आप हुक्मदेव जी को देख लीजिए, वे किस रूप में आए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे ठंडक से ज्यादा तकलीफ पाएं।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप ये शॉल उतारकर लालू जी को दे दीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: चादर उन्हीं के द्वारा दहेज में दी हुई है।

श्री सभापति: लालू जी, यह अच्छा नहीं है। आप पहले तो शॉल देकर ओढ़वाते हैं और फिर यहां क्वेश्चन रेज़ करते हैं, यह ठीक नहीं है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Mr. Chairman, Sir, we all know that the urban cooperative banks are very important for the progress of the middle class people and also of various small business sections. Unfortunately, some scams have taken place, and due to it a number of banks suffered heavy losses, and have shut their doors. I am very happy that the Reserve Bank of India has appointed a Screening Committee to check all these things and see to it that more care is taken in giving new licenses. My question here is this. Sir, a car should neither run at a speed of 150 kilometres per hour nor should it run at a speed of 20 killometres per hour. It should run at an average speed to reach the destination. But, what is the Government doing? Previously, you had given liberal sanctions. But, now, out of ninety proposals for giving new licenses, only two have been approved and eighty-eight have been rejected. I feel this is also not a good thing. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is taking more care to see to it that more and more banks with good credibility and background are encouraged, but, at the same time, to see to it that they won't go on wrong tracks. But it should not be done by putting more hurdles on their way and by rejecting all the licences. So, I would like to know what the Government is doing to encourage this sector. You are becoming more rigid by rejecting more proposals.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, the cooperative sector has to be encouraged. There is no question, and there are no two views about it, whether it is the urban cooperative or the rural cooperative. ...(*Interruptions*)... I am talking about both, about urban cooperatives also. It must be encouraged. But, I am sure the hon. Member would agree that while you encourage the cooperatives, because they are the agencies that provide credit to the farming sector, to agriculturists, to the small borrower,—it is very important—but, simultaneously, if there are any shortcomings in this sector, they must be eliminated. The hon. Member wanted to know at what speed you will travel at ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: No, no. Sorry. My question is this. Out of 90 proposals, you have rejected 88 proposals. Only two proposals have been approved. This speed is too slow. Previously, you were doing it liberally. Both the things are not good. Therefore, I wanted some sort of rational selection in it.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I understand that that could be interpreted as a suggestion. But I am not interpreting it as a suggestion. Out of 90 proposals, if only 88 are rejected, ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

SHRI JASWANT SINGH: If only two are approved, I can say that you can travel, Sir, at the speed at which the road permits you to travel. If the road is full of potholes, how will you travel faster? So, unless the road improves, you can't travel faster.

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस आर.बी.आई. देता है और उसकी मॉनीटरिंग स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करता है। आर.बी.आई. ने 88 ऐप्लीकेशन्स को रिजेक्ट किया लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या चेक आप कर रहे हैं क्योंकि they are still uncontrolled as far as the RBI is concerned. न आर.बी.आई. उनको देख रहा है, न कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देख रहा है। जो नए कंट्रोल आपने किए हैं, वे ठीक हैं लेकिन जो अभी ऐक्ज़िस्टिंग हैं, जिसमें लाखों लोगों की सारी जिंदगी की छोटी-छोटी कमाई जमा करवाते हैं अपने इंटरेस्ट के चक्कर में और फिर उनके साथ ऐम्बेज़लमेंट हो जाता है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: महोदय, यह प्रश्न वैसे पहले भी पूछा जा चुका है। मैं संक्षेप में माननीय सदस्य को बता दूं कि इसमें अर्बन कोऑपेरिव बैंकों के लिए जो क्लासिफिकेशन थे--वीक और

सिक्के--उनमें मॉडिफिकेशन लाया गया है और जो एक नया सिस्टम ग्रेडिंग का बनाया है, उसमें भी परिवर्तन लाया गया है। दूसरा, जो नॉन शेडयूल्ड कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको इजाज़त दी जा चुकी है कि वे अपने सरप्लस फंड्ज़ को जो स्ट्रांग शेडयूल्ड कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हों, उनके साथ रख सकें। तीसरा, उसके साथ जो सीलिंग लगाई गई हैं अनस्पेसिफाइड ऐडवांसेज़ पर, उस सीलिंग का रिवीज़न हुआ है। उसी के साथ, जैसार कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ''मॉनीटरी ऑफ क्रेडिट पॉलिसी 2003-04'' में घोषणा की जा चुकी है कि both gold loans and small loans up to Rs. One lakh will continue to be governed by the 80-day norm for recognition और इसी तरह अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को इजाज़त होगी कि वे नए एक्सटेंशन खोलने के लिए रेज़ीडेंशियल यानी जहां रहने की जगह है, वहां भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोल सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Transfer of Red Fort to ASI

*306. SHRI NANA DESHMUKH: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Army has already transferred portions of the Red Fort to the Archaeological Survey of India;

(b) whether it is also a fact that the complete charge would be handed over to the Archaeological Survey of India very soon; and

(c) if so, what steps have been taken by Government to conserve and restore the past glory of the Red Fort?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI JAGMOHAN): (a) to (c) On December 22, 2003 the Ministry of Defence/Army Headquarters have transferred the entire Red Fort monument to the Ministry of Tourism and Culture/Archaeological Survey of India. Previously, only about 30 percent of the Red Fort area was with the Archaeological Survey of India/Ministry of Tourism and Culture.